

[2023] 3 एस. सी. आर. 639

/

अवतार सिंह और ए. एन. आर.

पंजाब राज्य

(2011 की आपराधिक अपील सं. 1711) 23 मार्च, 2023

/

[अभय एस. ओका और राजेश बिंदल, जे. जे.]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955: धारा 7-दंड-गैस सिलेंडर के अनधिकृत कब्जे में अपीलकर्ता-दोषसिद्धि और यू/एस को सजा। 7, निचली अदालतों द्वारा-अपीलकर्ताओं का मामला कि गैस सिलेंडर पुलिस के उप-निरीक्षक द्वारा जब्त किया गया था, जो ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं थे-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: जहां किसी निश्चित तरीके से किसी विशेष कार्य को करने की शक्ति दी जाती है, तो उस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए या नहीं-अन्य तरीके अनिवार्य रूप से निषिद्ध हैं-आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उप-निरीक्षक के अधिकार और शक्ति के अभाव में, उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से अनधिकृत है और उसे निरस्त करना होगा-इस प्रकार, नीचे दी गई अदालतों द्वारा पारित आदेश-तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश, 1988-खंड 7 को दरकिनार कर दिया गया है।

/

/

धरणी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ

और ओआरएस। (2019) 5 एससीसी 480: [2019] 6 एस. सी. आर. 307-संदर्भित।

/

संदर्भित निर्णय

[2019] 6 एससीआर 307

संदर्भित

पैरा 15

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: 2011 की आपराधिक अपील सं. 1711।

/

1997 के सी. आर. एल. ए. No.562-SB में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से। सुश्री शालू शर्मा, विशाल अरुण मिश्रा, यू. एम. त्रिपाठी, सुश्री हर्षिता निगम, सौरभ शर्मा, किशोरीलाल प्यारेलाल गुप्ता, उज्जवल भारद्वाज, हितेश शाही, यशशवी शर्मा, खुशाल अग्रवाल, आयुष पंवार, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

/

करण शर्मा, ऋषभ शर्मा, मोहित सिवाच, रोहित कलियार, एड. प्रत्यर्थियों के लिए।

/

639 ए.

640

/

[2023] 3 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

राजेश बिंदल, जे।

1. 15 जनवरी, 2010 की आपराधिक अपील संख्या 562-एस. बी. अंतर्गत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय को इस अपील अंतर्गत चुनौती दी गई है।

/

2. अपीलार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अंतर्गत अपनी दोषसिद्धि से व्यथित हैं।

3. विचारण न्यायालय ने 8 जुलाई, 1997 के निर्णय और आदेश के माध्यम से अपीलार्थियों को दोषी ठहराया था और उन्हें 500/- रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने की अवधि के लिए कारावास से गुजरने का निर्देश दिया था।

/

4. तथ्य, जैसा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध है, यह है कि 26.02.1995 पर, पुलिस के उप-निरीक्षक अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बस स्टॉप, फगवाड़ा में मौजूद थे। उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि अपीलार्थी काले रंग में गैस सिलेंडर बेचने में लिप्त थे। वे '102/- (केवल एक सौ बाईस रुपये) की निर्धारित दर के बजाय' 250/- (केवल दो सौ पचास रुपये) ले रहे थे। उनके

ट्रक का नंबर। एचआर-05 ए-4918 को चावला ऑटो वर्कशॉप के सामने खड़ा किया गया था। जानकारी को विश्वसनीय पाते हुए, प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस अधिकारी मौके पर गए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

/

/

5. निचली विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य में, किसी भी स्वतंत्र गवाह या काले रंग के सिलेंडरों के कथित खरीदारों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष के पक्ष में केवल दो आधिकारिक गवाहों ने गवाही दी।

/

6. एकमात्र आरोप जो साबित किया जा सका वह था अनधिकृत रूप से गैस सिलेंडर रखना, जिसके आधार पर निचली विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और कारावास का आदेश दिया।

7. निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उच्च न्यायालय की अपील में बरकरार रखा गया था।

/

8. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 1988 दिनांक 08.03.1988 (इसके बाद 'आदेश' के रूप में संदर्भित) के संदर्भ में, प्रवेश और जब्ती आदेश के खंड 7 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। आदेश का खंड 7 ए को अधिकृत करता है

/

641

अवतार सिंह और ए. एन. आर. पंजाब राज्य [राजेश बिंदल, जे.] ए.

कुछ व्यक्तियों को किसी भी जहाज या वाहन को रोकने और तलाशी लेने के लिए, जिसके बारे में अधिकारी को विश्वास है कि आदेश के उल्लंघन में इसका उपयोग किया गया है या किया जा रहा है या होने वाला है।

9. आदेश का खंड 3 गैस सिलेंडरों के अनधिकृत कब्जे को प्रतिबंधित करता है। निवेदन यह है कि खंड 7 के अनुसार, सरकार का कोई अधिकारी या खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, जो ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निरीक्षक के पद से कम नहीं है, या कोई अधिकारी जो किसी तेल कंपनी के बिक्री अधिकारी के पद से कम नहीं है, या केंद्र

सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई व्यक्ति, आदेश के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कि इस आदेश या उसके तहत किए गए किसी आदेश का पालन किया गया है, ऐसी कवायद/जबती करने के लिए अधिकृत है।

/

/

10. हाथ में मामले में, पुलिस के उप-निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की गई है, जो सरकारी आदेश के अनुसार अधिकृत नहीं है। अतः अभियोजन पक्ष का पूरा मामला गिर जाता है। उपरोक्त तर्क पर न तो निचली अदालत ने और न ही उच्च न्यायालय ने विचार किया है।

/

11. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं को गैस सिलेंडरों के अनधिकृत कब्जे में पाया गया है। उन्हें सही तरीके से दोषी ठहराया गया है। केवल कुछ तकनीकी चूक के लिए, उन्हें स्कॉट-फ्री जाने की अनुज्ञात नहीं दी जानी चाहिए। उस समय गैस सिलेंडरों की भारी कमी थी और इसकी कालाबाजारी और अनधिकृत कब्जे की जांच के लिए आदेश जारी किए गए थे।

/

12. पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना और प्रासंगिक संदर्भित रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

/

13. मामले के तथ्य, जैसा कि ऊपर देखा गया है, विवाद में नहीं हैं। एकमात्र तर्क उस व्यक्ति की शक्ति के बारे में है जिसने सिलेंडर जब्त किया था जिसके आधार पर अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया था। आदेश का खंड 7, जिसे यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है, उन अधिकारियों को निर्धारित करता है जिनके पास शक्ति है।

/

“7. प्रवेश, तलाशी और जबती की शक्ति:-

(1) एक अधिकारी या सरकार का खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, जो ऐसी सरकार द्वारा अधिकृत और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निरीक्षक के पद से कम नहीं है या कोई अधिकारी जो बिक्री के पद से कम नहीं है।

/

किसी तेल कंपनी का अधिकारी, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्ति, इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कि इस आदेश या इसके तहत किए गए किसी आदेश का पालन किया गया है:

/

(क) किसी भी जहाज या वाहन को रोकें और उसकी तलाशी लें, जिसके बारे में अधिकारी को विश्वास है कि इस आदेश के उल्लंघन में इसका उपयोग किया गया है, या किया जा रहा है या होने वाला है।

(ख) ऐसी सहायता या सहायता के साथ किसी भी स्थान में प्रवेश करें या खोज करें जो आवश्यक हो;

/

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धाराओं के प्रावधानों के अंतर्गत कलेक्टर के समक्ष जब्त किए गए सिलेंडर, सिलेंडर, गैस सिलेंडर, दबाव नियामक, वाहन, जहाजों या अन्य परिवहनों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के भंडार के उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना या अधिकृत करना, यदि उसे संदेह है कि इस आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या होने वाला है, तो सिलेंडर, सिलेंडर वाल्व और दबाव नियामकों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के किसी भी भंडार की पूरी मात्रा को जब्त करना और निकालना और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धाराओं के प्रावधानों के प्रावधानों के अंतर्गत कलेक्टर के समक्ष इस तरह से जब्त किए गए सिलेंडर, गैस सिलेंडर वाल्व, दबाव नियामकों, वाहनों या अन्य परिवहनों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के भंडार के उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना या अधिकृत करना।

/

/

/

14. यह कहीं भी निर्धारित नहीं करता है कि पुलिस का एक उप-निरीक्षक कार्रवाई कर सकता है। निस्संदेह, उपरोक्त खंड में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट अधिकारियों के अलावा, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति आदेश के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। हालाँकि, इस तर्क के समर्थन में कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है कि पुलिस के उप-निरीक्षक को उपरोक्त आदेश के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया था। 15. यह एक स्थापित विधि है कि जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने की शक्ति दी जाती है, तो काम उस तरह से

किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। अन्य विधियों को अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित किया गया है। संदर्भ दिया जा सकता है

/

धरणी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य ने (2019) 5 एस. सी. सी. 480 में रिपोर्ट किया।

/

643

अवतार सिंह और ए. एन. आर. पंजाब राज्य [राजेश बिंदल, जे.]

/

16. उप-निरीक्षक के पास आदेश के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार और शक्ति के अभाव में, उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से अनधिकृत होगी और इसे रद्द करना होगा।

17. ऊपर बताए गए कारणों से, अपील की अनुज्ञात है। पंजाब और हरियाणा उच्च विचारण न्यायालय द्वारा 15 जनवरी, 2010 की आपराधिक अपील संख्या 562-एस. बी. में दिए गए निर्णय और निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया जाता है। जमानत बांड का भुगतान कर दिया जाता है।

/

/

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/